

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल बिल लाया गया और यह इतना खौफनाक, इतना भयानक और इतना खतरनाक कदम है कि अगर इसकी तरफ सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने तवज्जह नहीं दी तो पूरा हिन्दुस्तान फिरकापरस्ती की आग में झुलस जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है। मस्जिद के लिए कानून बनाकर कब्रिस्तान में मुर्दे को जमीन के अंदर गाड़ने के लिए...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rashid Alvi, you have given notice on lawyers strike but you are speaking on some other matter. You have to give a separate notice for this.

...(Interruptions)

SHRI RASHID ALVI : I agree with you, Sir, but this is a serious matter.

MR. SPEAKER: If you could stick to the matter given in your notice, you may speak. I will not allow you to raise other matters.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लॉयर्स के बारे में रज कर सकते हैं तो करिए।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसके बारे में मुझे सरकार से इतना कहना है कि प्रैसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर साइन न करें।...(व्यवधान)

महोदय, इस बारे में मैंने नोटिस दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार को मालूम है कि 15 दिनों से दिल्ली के अन्दर वकील हड़ताल पर हैं ? डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है। वकीलों के साथ सरकार ने ज्यादाती की है। क्या सरकार को मालूम है कि दो वकीलों ने अपनी आंखें खो दी हैं ? पुलिस ने वकीलों के साथ ज्यादाती की है। उन पर जिस तरीके से डंडा चलाया है, उससे दो वकील अपनी आंखें खो चुके हैं। जो लड़कियां वकालत करती हैं, उन्हें घसीट-घसीट कर मारा गया है। पुलिस ने सिर्फ यही नहीं किया है, उनके हाथों से निकली हुई अंगुठियां भी उठा ली गई हैं। सरकार 15 दिनों से खामोश तमाशाई बनी बैठी है और पुलिस तथा पुलिस आफिसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली में करीब-करीब एक लाख आदमी तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होता है और पचास हजार आदमी दूसरी अदालतों में हाजिर होता है। इस प्रकार डेढ़ लाख आदमी अदालतों में जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बना बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को पुलिस आफिसरों के खालिफ तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए और वकीलों से बातचीत करनी चाहिए। श्री रामजेठ मलानी, कानून मंत्री, सदन में बैठे हैं, उन्होंने सदन में यह कहा था कि हमने समझौता कर लिया है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। मुझसे आपने फरमाया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी बात तय हो गई है, लेकिन कोई बात तय नहीं हुई है। इसलिए मैं पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब उस DCP को तुरन्त सस्पेंड करें और साथ ही वकीलों से बातचीत करें।

इसके साथ ही मैं एक मुद्दे की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर **₹** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ramesh Chennithala to speak.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: You are not allowed to speak further. This will not go on record.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Shri Akhilesh, please take your seat. I have allowed Shri Ramesh Chennithala to speak .

...(Interruptions)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Shri Rashid Alvi, please take your seat now. You have submitted whatever you wanted to. Other hon. Members have to be given a chance.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, you are not allowing your Member to speak. I have called Shri Ramesh Chennithala to speak.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I have got to say only a few words. Do allow the hon. Members to associate themselves with this issue. This is a matter of grave concern. It really concerns every citizen of this country because lawyers are forced to go on strike not only here but all over the country. In a democracy, people should be called for discussions....(*Interruptions*)